गुजरात में कच्छ जिले के लिए स्वीकृत योजनाएं/परियोजनाएं

5357. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कच्छ जिले से संबंधित उन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जो राज्य सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक इनमें से कितनी योजनाओं/परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की है तथा कितनी योजनाएं और परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक योजना और परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता कोष से राशि आबंटित की है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कच्छ जिले में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान कच्छ जिले के विकास के लिए गुजरात सरकार द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं :

1. कच्छ जिले के लिए आई डब्ल्यू डी पी भाग-1
2. कच्छ जिले के लिए आई डब्ल्यू डी पी भाग-2
3. कच्छ के लिए जी ई डी ए द्वारा तैयार की गई आई डब्ल्यू डी पी ।
4. कच्छ लिगनाइट टी पी एस यूनिट 3—70 एम डब्ल्यू आफ जी ई बी.
5. 250 एकोमोट लिगनाइट बेस टी पी एस आफ जी पी सी एल
6. सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र को जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन परियोजना
7. नाल आपरेशन फ्लड प्रवर्तीय और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेरी विकास परियोजना

इसके अतिरिक्त कच्छ जिले के छह ताल्लुका सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं।

(ख) और (ग) क्रम संख्या 1, 2, 4 और 7 पर दी गई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और उनके लिए निधि उपलब्ध करा दी गई है। अन्य परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, विशेष रोजगार कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रमों के तहत कच्छ जिले में रोजगार सर्जन पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है।

MUSLIMS LIVING BELOW THE POVERTY LINE

5358. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) the number of people living below the poverty line in the country as on 31st March, 1994 State-wise details thereof; and